corporations and suggest to the Government the detailed parameters to be laid down by law subject to which the telecasting/broadcasting rights could be offered to public corporations.

Popuation below poverty line

538. DR. RATNAKAR PANDEY: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the estimated population, both rural and urban of the country below poverty line in 1970, 1980 and 1990 respectively;

(b) what was their State-wise break-up; and

(c) what remedias steps Government has taken to raise the living standard of the population which is living below the poverty line?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) and (b) State-wise and All-India estimates of population below poverty line, both rural and urban, for the years 1972-73, 1977-78, 1983-84 and 1987-88 are given in Annexure-I (a) to (d). Such estimates are not available for the years 1970, 1980 and 1990.

(See Appendix 160, Annexure No. 27)

(c) The States have been implementing development plans for raising the living standard of the population living below the poverty line. These plans include investment/outlay for the development of infrastructure, industry, agriculture, irrigation, rural development, education and health, and also for implementation of direct employment generation and poverty alleviation programmes, such as Integrated Rural Development Programme and Jawahar Rozgar Yojana.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप

539. डा० रत्नाकर पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद तथा अन्य सरकारी अनियमितताओं के आरोपों के बारे में ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग लगाने के लिए परमिट

540. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग लगाने के लिए कितने परमिट जारी किए गए हैं, और

(ख) इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि जारी की गई है और उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) भारत सरकार लघु उद्योग लगाने के लिए परमिट जारी नहीं करती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।